वनमंत्री व्दारा बस्तर विखं में 1.18 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन

✷ बस्तर के विकास के लिएं तेज गति से कार्य - केदार कश्यप

नारायणपुर 1 मई (दण्डकारण्य समाचार)। वनमंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के बस्तर विकास खंड में करोड़ों के विकास कार्यों का भूमिपूजन कर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे बस्तर संभाग के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार सहित केंद्र की मोदी सरकार भी बस्तरवासियों के साथ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के विकास कार्यों और नियद नेल्लानार जैसे योजनाओं के क्रियान्वयन से बस्तर नक्सल मुक्त क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा सपना अब साकार होने लगा है। भाजपा सरकार के नियद नेल्ला नार योजना ने बस्तर के उन क्षेत्रों में मूलभुत सुविधाओं और अवश्यकताओं को पूर्ण करने का कार्य किया है जहाँ आजादी के 70 साल बाद भी कांग्रेस की सरकार पहुंच नहीं पायी। वनमंत्री ने कहा कि हमारा बस्तर अब हर दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

सड़क, चबूतरा, सांस्कृतिक मंच, हाईमास्क लाईट की सौगात

वनमंत्री केदार कश्यप ने आज ग्राम पंचायत मांदलापाल, कुंगारपाल, बाकेल, भानपुरी में आंगनबाडी केंद्र, सांस्कृतिक मंच, चबूतरा, सीसी सड़क निर्माण, विभिन्न स्थानों पर हाई मास्क लाइट की व्यवस्था जैसे करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन कर क्षेत्र वासियों को 1 करोड़ 18 लाख रूपये का सौगात प्रदान किया है।

संतोषी भण्डारी का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भोपाल के लिए चयन

✷ बीजापुर की बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जिले का मान

बीजापुर 1 मई (दण्डकारण्य समाचार)। बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी की एथलेटिक्स खिलाड़ी संतोषी भण्डारी का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल के लिए किया गया है। यह चयन भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 24 अप्रैल 2025 को जारी की गई चयन सूची के आधार पर हुआ है, जिसमें देशभर की 10 बालिका एथलीट्स को उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चुना गया है।

संतोषी भण्डारी सूची में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं, जो बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बीजापुर की छात्रा हैं। उन्होंने हाल ही में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 11 से 14 जनवरी 2025 तक रांची झारखंड में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स में 400 मीटर और 600 मीटर दौड़ में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 400 मीटर में 1:02 मिनट और 600 मीटर में 1:41 मिनट का शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया स्तर पर 8वां स्थान प्राप्त किया।

इसके पूर्व, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 35वीं वेस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चौंपियनशिप जो 4 से 6 अक्टूबर 2024 को नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित हुई थी उसमें उन्होंने 4वां स्थान प्राप्त किया था।

भारतीय खेल प्राधिकरण हर वर्ष देशभर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें नेशनल सेंटर ऑफ एकसीलेंस में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और डाइट की सुविधा प्रदान करता है। संतोषी भण्डारी के इस उपलब्धि पर बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा ने उन्हें स्पोर्ट्स किट भेंट कर उज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर एवं जिला खेल अधिकारी एनपी गवेल सहित कोच संदीप गुप्ता उपस्थित रहे। बीजापुर जिले के लिए यह गौरव की बात है कि यहां की एक बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाकर जिले का नाम रोशन किया है।

स्थानीय लोगों के आर्थिक उत्थान सहित मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें- महेश कश्यप

✷ जिला खनिज न्यास शासी परिषद की बैठक में नये विकास कार्यों का हुआ अनुमोदन

दंतेवाड़ा, 1 मई (दण्डकारण्य समाचार)। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप जिला खनिज न्यास निधि के तहत प्रभावित इलाके के लोगों के आर्थिक उत्थान हेतु आजीविका के साधनों के विकास सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इसके साथ ही आवश्यकता के अनुरूप अधोसंरचना सम्बन्धी कार्यों तथा सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण, युवा गतिविधियों तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने सहित खनन प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिये राशि का प्रावधान किया गया है। अब जिला खनिज न्यास निधि का सदुपयोग कर जिले के समग्र विकास करने सकारात्मक पहल किया जायेगा। उक्त बातें बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कलेक्टोरेट के सभागार में आयोजित जिला खनिज न्यास शासी परिषद की बैठक के दौरान कही।

सांसद कश्यप ने आगे कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप दंतेवाड़ा जिले के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में जिले के विभिन्न विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि (डीएमएफ) के तहत दंतेवाड़ा जिले को अब तक 17 सौ करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसका उद्देश्य जिले के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना है। कश्यप ने कहा कि दंतेवाड़ा एक समृद्ध प्राकृतिक विरासत से परिपूर्ण जिला है, जहां जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदाएं भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। इन संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए, स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है।

शासी परिषद की बैठक के दौरान क्षेत्रीय विधायक चैतराम अटामी ने डीएमएफ (जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि) मद से स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे डीएमएफ मद से स्वीकृत सभी निर्माण व विकास परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करें, क्योंकि इन कार्यों में विलम्ब होने से जनता को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी ने जिला खनिज निधि से संचालित योजनाओं और कार्यों के क्रियान्वयन पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन निधियों का उपयोग केवल जरूरतमंद क्षेत्रों और प्राथमिकताओं के अनुसार ही किया जाए। उन्होंने कहा कि डीएमएफ की राशि जनता के कल्याण हेतु है, इसलिए इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। मुड़ामी ने विशेष रूप से पेयजल संकट की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि कई ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों से पेयजल की समस्या की जानकारी मिल रही है। इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करने और दीर्घकालिक समाधान हेतु योजना तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे क्षेत्रीय भ्रमण कर जमीनी हालात का जायजा लें और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता पर सुलझाएं।

जिला न्यायाधीश द्वारा उप-जेल का निरीक्षण

नारायणपुर, 1 मई (दण्डकारण्य समाचार)। 29 अप्रैल को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्रीमती किरण चतुर्वेदी के द्वारा उप जेल नारायणपुर का औचक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नारायणपुर, हरेन्द्र सिंह नाग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर कु. प्रतिभा मरकाम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव श्रीमती रेश्मा बैरागी पटेल एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव गायत्री साय उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान श्रीमती किरण चतुर्वेदी ने कारागार की विभिन्न व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया, जिसमें बैरकों की साफ-सफाई, भोजन की गुणवत्ता, चिकित्सा सुविधाए और बंदियों को प्रदान की जा रहीं अन्य सुविधाए शामिल थी। जेल में निरूद्ध बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की गई और उनकी शिकायतों का त्वरित निवारण करने के निर्देश दिए गए।

जिला न्यायाधीश ने जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि जेल मैनुअल के अनुसार सभी बंदियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। विशेष रूप से, जिन बंदियों के पास कानूनी सहायता के लिए अधिवक्ता नहीं है, उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से व्यवस्था की जाए। साथ ही बंदियों के नियमित स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सुविधाओं को और सुदृढ करने के निर्देश दिए गए। उक्त निरीक्षण में सहायक जेल अधीक्षक संजय नायक, चन्द्रप्रकाश कश्यप् अधिवक्ता, एवं पैरालीगल वालिंटियर, अधिकार मित्र घासी राम नेताम एवं प्रतिमा दोदी उपस्थित थे।

तेलंगाना एवं अन्य प्रान्तों में प्रवासित परिवारों के पुनर्वास प्रयोजन हेतु सर्वे

दंतेवाड़ा, 1 मई (दण्डकारण्य समाचार)। बस्तर क्षेत्र के सीमावर्ती तेलंगाना एवं अन्य प्रान्तों में प्रवासित परिवारों के पुनर्वास प्रयोजन हेतु सर्वे कार्य हेतु जिला प्रशासन द्वारा समिति गठित की गई हैं। इसके अन्तर्गत अधिकारी, कर्मचारियों को नोडल बनाया गया हैं। उपरोक्त टीम में प्रवासित परिवारों के पुनर्वास प्रयोजन हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर मूलचंद चोपड़ा के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जिला दंतेवाड़ा क्षेत्र के प्रवासित परिवारों के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं में सर्वे कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

गठित टीम द्वारा इस जिले से विस्थापित होकर निकटवर्ती प्रांतों में निवासरत प्रवासित परिवारों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार करने के साथ-साथ विस्थापित परिवारों से भेंट कर उनके वर्तमान निवास स्थान में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं, रोजगार एवं अन्य संसाधन के संबंध में प्रति परिवार का पृथक-पृथक प्रपत्र में जानकारी तैयार करने, इस जिले के विस्थापित परिवारों को उनके मूल निवास ग्राम (जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा) आने के लिये उन्हें शासन की पुनर्वास योजना एवं शासन की अन्य लाभकारी योजनाओं से अवगत कराते हुये मूल ग्राम वापस आने के लिए प्रेरित करने, विस्थापित परिवारों को उनके मूल निवास ग्राम (जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा) लाये जाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किए जाने, जैसे कार्य किया जावेगा। इसके साथ ही संपूर्ण सर्वे कार्य का सुव्यवस्थित दस्तावेजीकरण किया जावें साथ ही फोटो एवं वीडियोग्राफी टीम द्वारा की जावेगी।

सुशासन तिहार में मिली शौचालय की स्वीकृति, लाभार्थियों ने जताया आभार

बीजापुर 1 मई (दण्डकारण्य समाचार)। सुशासन तिहार के अवसर पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में जांगला निवासी श्रीमती सन्नी लेकाम द्वारा व्यक्तिगत शौचालय की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देश पर तत्परता दिखाते हुए संबंधित विभाग द्वारा तत्काल स्वीकृति प्रदान की गई। श्रीमती सन्नी लेकाम ने शासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह वास्तव में जनहित में तत्पर शासन की भावना को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनके परिवार को बहुत सुविधा मिलेगी। इसी क्रम में माटवाड़ा की श्रीमती तुलसी को भी सुशासन तिहार के दौरान शौचालय की सुविधा स्वीकृत की गई। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सुविधा उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। जिला प्रशासन की इस त्वरित एवं संवेदनशील कार्यप्रणाली से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया

पीएम आवास योजना मामले में सुकमा बस्तर संभाग में प्रथम स्थान पर

नियद नेल्लानार योजनांतर्गत 512 पीएम आवास में से 117 आवास पूर्ण

सुकमा, 1 मई (दण्डकारण्य समाचार)। सुकमा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के नेतृत्व एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता जैन की कड़ी मेहनत एवं सतत निगरानी के परिणामस्वरूप सुकमा जिला बस्तर संभाग मे आवास निर्माण कार्य, आवास की स्वीकृति, नियद नेल्लानार योजना मे आवास स्वीकृति एवं निर्माण कार्य, स्पेशल प्रोजेक्ट अंतर्गत आवास की स्वीकृति आदि बिंदुओ मे अव्वल स्थान पर है।

नियद नेल्लानार योजना के तहत निर्माण कार्यो मे आई तेजी

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता जैन के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2016-25 तक 1577 पात्र परिवारों मे से 512 हितग्राहियों का आवास स्वीकृत किया गया है जिसके विरुद्ध 117 आवास को पूर्ण का लिया गया है। जिला सीईओ श्रीमती जैन के द्वारा जनपद पंचायत सुकमा एवं कोंटा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शेष बचे हुए पात्र हितग्राहियों का आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करके सॉफ्टवेयर मे अतिशीघ्र पंजीयन करने के निर्देश दिये गए हैं।

मेंडपाल गांव बना हर घर जल प्रमाणित गांव

कोंडागांव, 1 मई (दण्डकारण्य समाचार)। जिले से लगभग 27 किलोमीटर दूर बसा छोटा-सा ग्राम मेंडपाल आज जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक मिसाल बन चुका है। कभी जहां गांव की महिलाएं किलोमीटरों दूर तालाब और हैंडपंप से पानी भरने के लिए जाती थीं, आज उसी गांव के हर घर में नल से स्वच्छ जल उपलब्ध है। यह परिवर्तन जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन और ग्रामवासियों की मजबूत जनभागीदारी का परिणाम है।

पहले पानी की किल्लत न केवल महिलाओं की दिनचर्या को प्रभावित करती थी, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती थी।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत हुए इस परिवर्तन से न केवल महिलाओं को बड़ी राहत मिली है, बल्कि बच्चों, बुजुर्गों और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आया है। अब महिलाएं घर के अन्य कार्यों पर ध्यान दे पा रही हैं, बच्चे समय पर स्कूल पहुंच पा रहे हैं और बुजुर्गों को दूर-दराज पानी ढोने की कठिनाइयों से मुक्ति मिली है।

ग्राम मेंडपाल में फूलमती, ललिता, सुनीता, सावित्री और केसरी जैसी महिलाएं %जल वाहिनी% के रूप में सक्रिय हैं। ये महिलाएं न केवल जल की गुणवत्ता की जांच करती हैं बल्कि स्वच्छता, जल संरक्षण और जल जनित बीमारियों से बचाव के प्रति गांव को निरंतर जागरूक भी कर रही हैं। जल जीवन मिशन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है, जिससे वे अब समाज के विकास में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

ग्राम मेंडपाल की एक विशेषता यह भी है कि जल आपूर्ति प्रणाली का संचालन और रखरखाव स्वयं ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा है। हर महीने प्रत्येक घर से जल शुल्क एकत्र कर योजनाबद्ध ढंग से इस व्यवस्था को स्थायी बनाया गया है। इससे न केवल सिस्टम की मजबूती बनी है, बल्कि आत्मनिर्भरता और सामुदायिक स्वामित्व की भावना भी गहरी हुई है।

प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों के परिजन को 12 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

बीजापुर 1 मई (दण्डकारण्य समाचार)। कलेक्टर संबित मिश्रा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों के परिजनों को 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अन्तर्गत नदी-नाले एवं तालाब के पानी में डुबने से मृत्यु के प्रकरण में मृतक लखु ओयाम के निकटतम वारिस उनकी पत्नि श्रीमती पोदिये आयोम, मृतक पुनेम रमेश के निकटतम वारिस श्रीमती पुनेम सदना एवं मृतक मुकेश उरसा के निकटतम वारिस लक्खू उरसा को 4-4 लाख रूपए कुल 3 पीड़ितों के परिजनों को 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति दी गई है। राशि का भुगतान संबंधित हितग्राही के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए गए हैं।

लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के साथ बैठक

नारायणपुर, 1 मई (दण्डकारण्य समाचार)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार आगामी नेशनल लोक अदालत जो 10 मई को आयोजित होने जा रही है। आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्रीमती किरण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में 29 अप्रैल को व्यवहार न्यायालय नारायणपुर में न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक का मुख्य उददेश्य नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों, जैसे मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 बैंक वसूली, श्रम विवाद और प्री-लिटिगेशन मामलों तथा न्यायालय में पेंडिग मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करना था। जिला न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं से अपने पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों, जैसे शीघ्र न्याय, कोर्ट फीस की वापसी, और अंतिम निर्णय की अपील न होने की सुविधा, के बारे में बताए जाने व जागरूक करने कहा गया।

उक्त बैठक में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश हरेन्द्र सिंह नाग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कु. प्रतिभा मरकाम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव रेश्मा बैरागी पटेल एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गायत्री साय तथा समस्त अधिवक्तागण उपस्थित थे।